बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 232 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 16 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

मुंबई में भारी बारिश, ट्रैक डूबने से लोकल ट्रेनें लेट

नई दिल्ली । मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सोमवार को सुबह से लगातार बारिश के कारण मुंबई में कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया। अंधेरी सबवे में डेढ़ फीट तक पानी भर जाने से पुलिस ने इसे बंद कर दिया। दादर, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें 10-15 मिनट देरी से चल रही हैं। हैदराबाद में भी तेज बारिश जारी है। हबीब नगर इलाके में रविवार रात भारी बारिश के बाद दो लोग बाढ़ में बह गए। तीन डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन इलाके में पानी का बहाव अभी भी तेज है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तय समय से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है।

1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर ढेर, अमित शाह बोले- पूरे देश से खत्म होगा नक्सलवाद

नई दिल्ली । झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी नेता और दो अन्य वरिष्ठ माओवादियों को मार गिराया गया। मारे गए कमांडर की पहचान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य सहदेव सोरेन के रूप में हुई है।

वह पूर्वी भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में से एक था। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता करार दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज झारखंड के हज़ारीबाग में सीआरपीएफ़ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान में एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर, सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ़ परवेश को ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा, दो अन्य इनामी नक्सली- रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ़ चंचल और बीरसेन गंझू उर्फ़ रामखेलावन - भी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए हैं। इस अभियान के बाद, उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। झारखंड पुलिस के अनुसार, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कोबरा बटालियन, गिरिडीह पुलिस और हज़ारीबाग पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। गिरिडीह-बोकारो सीमा के पास टाटीझरिया थाना क्षेत्र के करंडी गाँव में सुबह लगभग 6 बजे गोलीबारी शुरू हुई। मुठभेड़ में दो अन्य माओवादी नेता बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का 25 लाख रुपये का इनामी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपये का इनामी जोनल कमेटी सदस्य बीरसेन गंझू उर्फ रामखेलावन भी मारे गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तीनों उग्रवादियों के शव बरामद कर लिए। अधिकारियों ने बताया कि जंगली इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है।

पीड़ितों के साथ हर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा है - राहुल गांधी

पंजाब।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि गांधी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित परिवारों से बातचीत की और राहत कार्यों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने गुरदासपुर में भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों से भी मुलाकात की।

पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। राज्य को जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने लिखा कि स्थिति बेहद विकट है। ऐसे कठिन समय में,

राहुल गांधी ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझा

हर कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाब के साथ खड़ा है। हम सभी से बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने की अपील करते हैं। इस आपदा से उबरने के लिए हमें एकजुट होना होगा। अपने दौरे के दौरान, कांग्रेस नेता परगट सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि राहुल गांधी पंजाब के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल जी पंजाब के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। वह अजनाला में प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जहाँ वह एक गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर प्रभावित किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। पंजाब में आई बाढ़ के बारे में बात करते हुए, सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि 1200 करोड़ रुपये का एसडीआरएफ फंड कहाँ खर्च किया गया। सिंह ने आगे कहा कि राय के लिए निर्धारित 1200 करोड़ रुपये के एसडीआरएफ फंड और उसके खर्च के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है... हमें उन लोगों की मदद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्होंने अपनी संपत्ति और सामान खो दिया है। इस बीच, राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए, पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा पंजाब पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सिद्धू ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है... वह हमारे लिए सबसे बड़े नेता हैं, और वह हमें सेवा करते रहने का निर्देश देते रहे। हम ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, वह घर बैठे अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। जब कोई वरिष्ठ नेता आपकी ओर ध्यान देता है, तो इससे आपको और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन उन्होंने राय की सत्तारूढ़ सरकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि अधिकारियों ने नदी के पास घरों के निर्माण की अनुमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार में पानी छोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए।

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

नशा मुक्त भारत 2047-एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एनसीओआरडी की भूमिका-एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत एक ऐसे युग से गुजर रहा है जहां विकास, आधुनिकता और वैश्वीकरण की चुनौतियाँ समानांतर रूप से सामने खड़ी हैं। इनमें सबसे खतरनाक और जटिल समस्या मादक पदार्थों (ड्रग्स) की है। यह समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनियाँ के लिए एक गंभीरसंकट है। मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि,ड्रग्स का अवैध कारोबार और उसका सेवन समाज की जड़ों को खोखला करता है, युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गहरा असर डालता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने नशा मुक्त भारत 2047 का लक्ष्य तय किया है, जो आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक एक ऐसे भारत की परिकल्पना करता है जहाँ मादक पदार्थों का अवैध कारोबार और सेवन पूरी तरह समाप्त हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटी एफ), एनसीओआरडी (नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ड्रग्स नार्कोटिक्स मैकेनिज्म)और नार्कोटिक्स कंट्रोलब्यूरो (एनसीबी) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।ड्रग्स की समस्या केवल सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ी है। ड्रग्स का पैसा आतंकी संगठनों और संगठित अपराध के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह खतरा और भी गंभीर है क्योंकि इसके पड़ोसी देशों में ड्रग्स उत्पादन और तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। गोल्डन ट्राएंगल और गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र से भारत में ड्रग्स की तस्करी लंबे समय से होती रही हैइसीलिए भारत की एंटी नार्कोटिक्स नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैंक्योंकि आगामी 16-17 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एकऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रमुख,अन्य सरकारी विभागों के हितधारक तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नशा मुक्त भारत 2047 के विज़न को ठोस आधार प्रदान करेगा और आने वाले वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करेगा।भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटी एफ)को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थों के खिलाफ एक संयुक्त तंत्र के रूप में गठित किया गया है।यह तंत्र आपूर्ति कम करने, मांग को नियंत्रित करने और नुकसान कम करने की नीति पर एक साथ काम करता है। एएनटीएफ का उद्देश्य केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में जागरूकता, शिक्षा और पुनर्वास को भी समान प्राथमिकता देना है। भारत के पीएम ने कई मौकों पर कहा है कि नशा समाज को खोखला कर देता है और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री की अगुवाई में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों बात अगर हम सम्मेलन का विषय संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी की करें तो इस द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी रखा गया है। यह विषय अपने आप में मादक पदार्थों की समस्या के समाधान का मूल मंत्र है। ड्रग्स की समस्या केवल एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज, सरकार और नागरिकों का सामूहिक दायित्व है। आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुलिस,सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल और कस्टम विभाग को मिलकर काम करना होगा। मांग कम करने के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठन अहम भूमिका निभाएँगे। नुकसान कम करने के लिए पुनर्वास केंद्र, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक सक्रिय योगदान देंगे। इस प्रकार यह समस्या एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती है जिसे केवल साझा जिम्मेदारी के सिद्धांत से ही सफल बनाया जा सकता है। साथियों बात अगर हम,2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में तकनीकी सत्रआठ विशेष विमर्श की करें तो भविष्य का रोडमैप और नीति निर्धारण- 2047 तक नशा मुक्त भारत का विज़न पूरा करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर मंथन होगा। ये आठ सत्र न केवल समस्या की गहराई को समझने का अवसर देंगे बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी सुझाएँगे। (1)सम्मेलन के दौरान आठ तकनीकी सत्र (टेक्निकल सेशंस)आयोजित किए जाएँगे। इनका उद्देश्य विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा और रणनीति बनाना है।(2)ड्रग्स आपूर्ति श्रृंखला की रोकथाम- इसमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क, सीमा पार तस्करी, डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले कारोबार को रोकने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। (3)ड्रग्स की मांग कम करने की रणनीति -शिक्षा, जागरूकता, युवाओं को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर विचार किया जाएगा (4)नुकसान कम करने के उपाय-नशा करने वालों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक उपचार की दिशा में कदमों पर चर्चा होगी। (5) राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्रग्स का संबंध-ड्रग्स से होने वाली आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। (6)कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाना- पुलिस, एनसीबी और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विमर्श होगा। (7) ड्रग्स और साइबर अपराध- डार्क वेब, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों पर चर्चा होगी।

(8) अंतरराष्ट्रीय सहयोग- पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग, सूचना साझा करने और संयुक्त अभियानों पर विचार होगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट-2024 जारी करेंगे। इस रिपोर्ट में बीते वर्ष में ड्रग्स की जब्ती, गिरफ्तारियाँ, अवैध नेटवर्क का खुलासा और निवारक कदमों का विस्तृत विवरण होगा। साथ ही, श्री शाह ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान (ड्रग डिस्पोजल कैंपेन) की शुरुआत करेंगे। यह अभियान एक अनोखी पहल होगी जिसमें जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। साथियों बात अगर हम,आपूर्ति, मांग और नुकसान कम करने की रणनीति तथा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की करें तोमादक पदार्थों की समस्या को तीन स्तरों पर समझा जाता है-(1)आपूर्ति कम करना-यानी ड्रग्स की तस्करी, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण।(2)मांग कम करना-यानी समाज में नशे की लत को रोकना और जागरूकता फैलाना(3) नुकसान कम करना-यानी नशे के शिकार लोगों का इलाज और पुनर्वास। भारत ने इन तीनों स्तरों पर रणनीतियाँ अपनाई हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ाना, ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कस्टम और पुलिस को मजबूत करना आपूर्ति रोकने की दिशा में अहम कदम है। मांग कम करने के लिए युवाओं में खेलकूद, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं नुकसान कम करने के लिए, पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया जा रहा है।

होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच-इस समस्या से निपटने के लिए केवल गृह मंत्रालय या एनसीबी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए एक होल ऑफ़ द गवर्नमेंट एप्रोच की आवश्यकता है। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग-शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और विदेश मंत्रालय-सभी को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओस) , नागरिक समाज और मीडिया की भी अहम भूमिका होगी। तभी यह लड़ाई व्यापक और सफल हो सकेगी। साथियों बात अगर हम पहले सम्मेलन (अप्रैल 2023) और उसकी उपलब्धियों व राष्ट्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थ को समझने की करें तो,अप्रैल 2023 में पहली बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटी एफ प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था।उस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिनमें प्रमुख थे,(1) सभी राज्यों में विशेष एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट का गठन। (2)ड्रग्स जब्ती और तस्करी से जुड़े जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रीय डेटा बैंक की स्थापना। (3)सीमा पार से होने वाली तस्करी पर रोक के लिए सीमा सुरक्षा बलों और एनसीबी के संयुक्त अभियान। (4)युवाओं और छात्रों में जागरूकता के लिए स्कूल-विश्वविद्यालय आधारित अभियान। (5)जब्त मादक पदार्थों का समयबद्ध निपटान। इनमें से लगभग 70-75 प्रतिशत निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में विशेष एएनटीएफ, इकाइयाँ बन चुकी हैं, बड़े पैमाने पर ड्रग्स की जब्ती हुई है, और राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स कीसूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक प्रभावी हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों जैसे सीमा पार तस्करी और ऑनलाइन ड्रग्स कारोबार में चुनौतियाँ बाकी हैं, जिन्हें इस दूसरे सम्मेलन में प्राथमिकता दी जाएगी। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे किभारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का जो लक्ष्य तय किया है, वह कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं।

सम्पादकीय...

भारत की स्वदेशी पहचान

पूरी दुनिया इन दिनों 'टैरिफ वॉर के चक्रव्यूह' में उलझी है। हर देश अपने-अपने हितों को साधने के लिए आयात-निर्यात पर शुल्क की दीवारें खड़ी कर रहा है। वैश्विक कूटनीति के इस दौर में आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने नए तनाव पैदा किए हैं और वैश्विक व्यापार का संतुलन डगमगा रहा है। प्रत्येक देश इस चक्रव्यूह को भेदने के रास्ते खोज रहा है, लेकिन इससे निकलने के लिए भारत के पास पूर्व में आजमाया हुआ एक शाश्वत समाधान है- स्वदेशी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दक्षिण अफ्रीका से लौटकर पूज्य बापू ने चरखे के माध्यम से स्वदेशी से स्वावलंबन का बिगुल फूंका था। आज वही चरखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से 'स्वदेशी क्रांति' का आधार बन गया है। हाल ही में गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री जी ने कहा था- गुजरात की ये धरती दो मोहन की है- एक सुदर्शन-चक्रधारी द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे चरखाधारी मोहन, साबरमती के संत पूज्य बापू। इन दोनों के मार्गदर्शन पर भारत निरंतर सशक्त हो रहा है। सच्चे अर्थों में मैं कहूं तो खादी के माध्यम से 'स्वदेशी क्रांति का ये मोदी युग है'। आज जब गांवों में चरखे-करघे की घरघराहट गूंजती है, तो उसमें केवल सूत नहीं, बल्कि विकसित भारत की आत्मा का ताना-बाना बुनता है। जिस चरखे को महात्मा गांधी ने 'आजादी का अस्त्र' बनाया था, उसी चरखे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत का आधार' बना दिया है। खादी अब केवल वस्त्र नहीं, बल्कि 'स्वदेशी क्रांति की ध्वजवाहक' बन चुकी है। स्वदेशी क्रांति के अगुवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंचों से लगातार देशवासियों से खादी और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान करते रहे हैं। 31 अगस्त, 2025 को 'मन की बात' में उन्होंने कहा-आने वाले दिनों में त्यौहारों की रौनक होगी। इन त्यौहारों में स्वदेशी को कभी न भूलें- उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामानों से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो। जीवन की हर जरूरत में स्वदेशी हो और गर्व से कहो- ये स्वदेशी है। इसी तरह से उन्होंने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले से संबोधन के दौरान सभी दुकानदारों व व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाएं जिसमें लिखा हो, 'यहां स्वदेशी माल बिकता है'। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा–जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब उसे सिद्ध कर दिखाया है। खादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खादी विलुप्त होने के कगार पर थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जब मुझे सेवा का अवसर मिला, मैंने देश से आह्वान किया और लोगों ने संकल्प लिया। नतीजा यह हुआ कि एक दशक में खादी की बिक्री लगभग सात गुना बढ़ी है। देशवासियों ने 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। भारत में यह समय तीज और त्यौहारों का है। प्रधानमंत्री की अपील है कि यह त्यौहारों का मौसम केवल संस्कृति का उत्सव न होकर आत्मनिर्भरता का उत्सव भी बने। उनका मंत्र साफ है- हम जो भी खरीदेंगे, वह मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा और जो भी बेचेंगे वो भी स्वदेशी होगा।'' आइए हम सभी आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने जैसे संदेशों के साथ अमृतकाल का विकसित और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लें। ध्यान रहे कि, विकसित भारत की नींव हमें, अपनी-अपनी इकाई से ही रखनी होगी। हम 144 करोड़ भारतवासी संकल्प लें कि हम स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदेंगे और बेचेंगे, जो एक स्वावलंबी, समृद्धि- शाली राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। बीते 11 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। कारोबार पहली बार पौने दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। खादी की बिक्री में सात गुना तक की वृद्धि हुई है। आज देशभर में लगभग 2 करोड़ लोग खादी और ग्रामोद्योग से जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि 'स्वदेशी क्रांति' का जीवंत प्रमाण है। मोदी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग न केवल 'वोकल फॉर लोकल' का अगुवा है, बल्कि 'मेक इन इंडिया', 'मेक फॉर द वर्ल्ड 'की जीवंत मिसाल भी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' से लेकर संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक हर जगह खादी का गौरवगान किया है। उन्होंने कहा है- जब आप खादी खरीदते हैं, तो यह सिर्फ वस्त्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को संबल देने वाला कदम होता है। यही खादी आज 'विकसित भारत @2047' अभियान का आधार बन गई है। राष्ट्र प्रथम की नीति और वंचितों के हितों की भावना से प्रेरित हमारे प्रधानसेवक सदैव लघु उद्यमियों, पशुपालकों, किसानों और श्रमजीवी भाइयों-बहनों की चिंता करते रहे हैं। अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के ऐसे विलक्षण नेता हैं, जो अपने छोटे कारोबारियों और हस्तशिल्पियों के उत्पादों को स्वयं प्रोत्साहित और प्रचारित करते हैं। इतना सशक्त और स्पष्ट संदेश केवल वही दे सकते हैं कि 'देश के उत्पादन में देशवासियों का पसीना झलके।' यही भावना 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' के संकल्प को जीवंत बनाती है। आज हम सबका एक ही मंत्र होना चाहिए- 'एक ही संकल्प, स्वदेशी विकल्प'- 'हर त्यौहार, सिर्फ स्वदेशी उपहार' अभी भारत के धैर्य की परीक्षा का समय है लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। चरखे का पहिया निरंतर गति से घूम रहा है। भारतीय जनमानस का खून-पसीना पूरे उत्साह और सामर्थ्य से अर्थव्यवस्था को सींच रहा है। यही सामर्थ्य विकसित भारत की गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचाएगा, जहां विश्व की महाशक्तियां भी भारत की विराट शक्ति को स्वीकारेंगी। आज नहीं तो कल, भारत को 'विश्व गुरु' के रूप में मान्यता मिलकर रहेगी।

टीवी बहसों का गिरता स्तर चिंतनीय

चैनल और एंकर ऐसे निरर्थक बहसों को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्या यह टीआरपी की होड़ है या राजनीतिक दबाव? टीवी बहसों का इतिहास भारत में 1990 के दशक से जुड़ा है, जब निजी चैनलों का आगमन हुआ।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संवाद और विमर्श लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं, वहां आज टीवी बहसें एक ऐसा मंच बन चुकी हैं जहां तर्क की जगह एक दूसरे का अपमान, चीख-पुकार और राजनीतिक दुष्प्रचार हावी हो गया है। प्राइम टाइम के इन शो में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आते हैं जिससे बहसें निष्कर्षहीन हो जाती हैं। यह न केवल दर्शकों के समय की बर्बादी है, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला एक खतरनाक माध्यम भी बन गया है। प्रवक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा ने टीवी डिबेट्स को एक सर्कस का रूप दे दिया है। चैनल और एंकर ऐसे निरर्थक बहसों को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्या यह टीआरपी की होड़ है या राजनीतिक दबाव? टीवी बहसों का इतिहास भारत में 1990 के दशक से जुड़ा है, जब निजी चैनलों का आगमन हुआ। शुरू में ये बहसें मुद्दों पर तथ्यपरक चर्चा का माध्यम थीं लेकिन आज ये एक शोरगुल भरी जंग बन चुकी हैं। विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से स्पष्ट है कि भारतीय टीवी डिबेट्स में आक्रामकता और विषाक्त भाषा का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा है। एक शोध के अनुसार, बहसों में एंकरों द्वारा आक्रामक लहजे का इस्तेमाल 80 प्रतिशत से अधिक होता है जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। ये आंकड़े बताते हैं कि बहसें अब सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि प्रचार का हथियार बन चुकी हैं। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग इस समस्या का केंद्रीय बिंदु है। एक बहस के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को दूसरी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा 'जयचंद' और 'गद्दार' कहा गया, जिसे सुनकर उस प्रवक्ता को हार्टअटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना टीवी डिबेट्स की विषाक्तता का जीता-जागता उदाहरण है। इसी तरह अन्य प्रवक्ता ने एक दूसरे प्रवक्ता को 'नाली का कीड़ा', 'दादी मां', 'वैंप' कहा या 'उल्टा टांग दूंगा' जैसे शब्दों का प्रयोग करते पाए गए हैं। एक प्रवक्ता ने तो बहस के दौरान दूसरे प्रवक्ता पर हाथ भी उठा दिया। यह समस्या बढ़ रही है, कम नहीं हुई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक टीवी बहस के दौरान एक नेता पर कुर्सी फेंकी गई, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। नवंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टीवी चैनल को एक प्रवक्ता के खिलाफ अपमानजनक क्लिप हटाने का आदेश दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अपमान अब शारीरिक हिंसा तक पहुंच गया है। राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे प्रवक्ताओं को चुना जाना भी एक चिंताजनक बात है। अधिकांश प्रवक्ता राजनीतिक अनुभव की कमी रखते हैं और केवल टीवी पर चिल्लाने के लिए नियुक्त होते हैं। यदि राजनीतिक दल द्वारा योग्य प्रवक्ताओं को चुना गया होता तो बहसें अधिक सभ्य और उत्पादक होतीं लेकिन वर्तमान में ये प्रवक्ता दलों के चेहरे बन चुके हैं, जो विचारधारा के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर निर्भर हैं। ऐसे स्तरहीन प्रवक्ताओं को चैनल क्यों आमंत्रित करते हैं? इसका मुख्य कारण टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट) है। शोरगुल भरी बहसें दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं, क्योंकि वे मनोरंजन का रूप ले लेती हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक दबावों के कारण ग्राउंड रिपोर्टिंग कम हो गई है और स्टूडियो डिबेट्स ही मुख्य सामग्री बन गई हैं। चैनल जानते हैं कि तर्कपूर्ण चर्चा से दर्शक भागते हैं लेकिन चीख-पुकार उन्हें बांधे रखती है। चैनल और एंकरों की जिम्मेदारी यहां महत्वपूर्ण है। वे मॉडरेटर हैं, न कि भागीदार लेकिन अधिकांश एंकर, खुद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रेडिफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बहसें 'विषैली' हो चुकी हैं। एंकर विपक्ष को बोलने न देकर, मात्र समय काटते हैं। यदि चैनल सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें तो स्थिति सुधर सकती है लेकिन टीआरपी और राजनीतिक लाभ के लालच में वे अनदेखी करते हैं। उसमाधान के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी हैं। सबसे पहले राजनैतिक दलों को प्रवक्ताओं के चयन में सुधार करना चाहिए। केवल अनुभवी और सभ्य व्यक्तियों को ही टीवी पर भेजा जाए। दूसरा, 'ट्राई' और सूचना मंत्रालय को सख्त नियम लागू करने चाहिए, जैसे अपमानजनक भाषा पर तत्काल जुर्माना लगे। तीसरा, दर्शकों को जागरूक होना चाहिए। वे ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें जो सनसनी फैलाते हैं। चौथा, स्वतंत्र मीडिया वॉचडॉग को मजबूत बनाना चाहिए। अंत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब पर तथ्यपरक बहसें बढ़ावा दें, जहां सोशल मीडिया इंगेजमेंट सकारात्मक हो। भारत की टीवी बहसें लोकतंत्र का मजाक बन चुकी हैं। अपमानजनक प्रवक्ताओं का बोलबाला न केवल बहसों को निरर्थक बनाता है, बल्कि समाज को विभाजित करता है। चैनल और एंकरों को यदि वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान करना है तो उन्हें टीआरपी के पीछे भागना छोड़कर जिम्मेदार संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा, ये बहसें लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती रहेंगी। समय आ गया है कि हम एक ऐसे मीडिया की मांग करें जहां तर्क जीते, न कि अपमान। केवल तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा।

नेपाल के जेन-ज़ी को भारत के जेन-ज़ी से सीखना चाहिए

नेपाल में गद्दी पलट गई। मतलब तख्ता पलट हो गया। या फिर कहें कि तख्ता पलट कर दिया गया। वही हो गया जो हम हमारे यहाँ हर समय गाते रहते है, सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है। लेकिन वहाँ के नौजवानों को पता है, गीत गाने से कुछ नहीं होता है। सिंहासन खाली करवाना पड़ता है। जनता को जा कर सिंहासन खाली करवाना पड़ता है। ऐसा इससे पहले बांग्लादेश में भी हुआ, और उससे पहले श्रीलंका में। तीनों देशों में बेरोजगारी थी, महंगाई थी। और वहाँ के हुक्मरानों के बच्चे, एक प्रतिशत लोगों के बच्चे, खूब ऐश का जीवन जी रहे थे जबकि जनता गरीबी में जी रही थी। तो गरीब जनता आ गई, सिंहासन खाली कराने। लोगों को डर है, हमारे यहाँ भी ऐसा हो न हो जाये। लेकिन उनका यह डर बेकार ही है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है ही कहाँ। बेरोजगारी तो बिल्कुल ही नहीं है। हर हाथ को रोजगार मिला हुआ है। हर हाथ में फोन है और हर फोन में रील है। और रील बनाने और देखने का रोजगार है। वहाँ की सरकार ने यही गड़बड़ी की। कई सारे सोशल प्लेटफार्म बंद कर दिये। नौजवान बेकार हो गए। हाथ में फोन तो है पर फोन में कुछ नहीं है। रील देखे तो कहाँ देखे। रील बना तो ले पर पोस्ट कहाँ करे। पर हमारे यहाँ सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है। एक दो बार चीन से दुश्मनी के चलते टिक टाक को बंद भी किया था तो जल्दी ही खोल दिया। सरकार से लोगों की बेचारगी देखी नहीं जाती हैं। सरकार को पता है, बेरोजगारों के लिए यह एक रोजगार है। रील बनाना और रील देखना। फोन से सम्बंधित एक और रोजगार सरकार जी की पार्टी ने लोगों को दिया हुआ है। फॉरवर्ड करने का। आई टी सेल के मैसेज फॉरवर्ड करने का। सुनते है, एक फॉरवर्ड के दो रुपये मिलते हैं। एक दिन में सौ मैसेज भी फॉरवर्ड कर दिये तो दो सौ रुपये तो पक्के। नेपाल के युवाओं को हमारे युवाओं से सीख लेनी चाहिए थी। युवा हमारे यहाँ भी बहुत हैं। बेरोजगारी भी बहुत है। महंगाई भी बहुत है। राजनेताओं और बड़े सेठों के बच्चे हमारे यहाँ भी ऐश का जीवन जीते हैं। किसी का बेटा क्रिकेट का सेठ बना बैठा है तो किसी के बच्चे पेट्रोल में एथनोल की मिलावट कर रहे हैं। किसी ने तो अपना चिड़िया घर ही बना डाला है। और हम चार पांच हजार करोड़ की शादी देख मस्त हो रहे हैं। उसकी रील, वीडियो से फॉरवर्ड फॉरवर्ड का खेल खेल रहे हैं। नेपाल के युवाओं को हमसे जो सीखना चाहिए वह है सहन शक्ति। हमारी सब कुछ सहने की शक्ति। नेपाली हमारे भाई हैं। वे पहले हिन्दू राष्ट्र थे और उन्होंने उसका चोला 2008 में उतार फेंका था। हम हिन्दू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। इस मामले में वे हमसे सीनियर हुए। शेष सभी मामलों में हम उनसे सीनियर हैं। हम उनके बड़े भाई हैं। हम उनके ही नहीं, सभी पड़ोसियों के बड़े भाई हैं। उन पर खूब धौंस जमाते हैं। हाँ तो, नेपाल के युवा हम से सीख सकते हैं कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को कैसे सह सकते हैं। कैसे अपने यहाँ के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बर्बाद होते देख सकते है ।

इस हवेली में आती है हर वर्ष एक आत्मा

उन दिनों ऐसा पहली बार हुआ था कि तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने अपने स्टाफ को, बाबू बाल मुकुंद गुप्त के सम्पादकीय लेखों और उनके नियमित स्तम्भ 'शिव शम्भू के चिट्ठे' का अंग्रेजी अनुवाद दैनिक आधार पर उन्हें भेजने का आदेश दिया था। कलकत्ता-प्रवास के मध्य हिंदी के महान विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त का टकराव हो जाया करता था लेकिन अधिकांश अवसरों पर द्विवेदी जी को ही झुकना पड़ता था। कहां गुड़ियानी का ग्रामीण युवा पत्रकार और कहां भाषा-मर्मज्ञ आचार्य द्विवेदी। बहरहाल, खूब चर्चा होती गुप्त जी की। इसी बीच उन्होंने बंगला की कृतियों के हिंदी अनुवाद का सिलसिला भी शुरू कर दिया। काम के बोझ से शरीर शीघ्र ही हारने लगा था। एक बार उनको लगा कि अब लम्बी पारी नहीं खेल पाएंगे तो उन्होंने अपने गांव गुड़ियानी लौटने का मन बना दिया। कोलकाता से तो यही कहकर अवकाश लिया था कि वापिस लौट आएंगे लेकिन मन में यही आशंका थी कि शायद शरीर इतना श्रम झेल नहीं पाएगा। पिछले कुछ दशकों से बाबू जी के दीवाने हर वर्ष उसी हवेली में हवन करते हैं और फिर शहर में एक समारोह। मगरअब धीरे-धीरे हवेली की हालत खराब होने लगी है और जहां बैठकर बाबू जी कलम-क्रांति करते थे वह स्थल भी ध्वस्त होने लगा है। वंशज कोलकाता में रहते हैं।

हरियाणा के जिला झज्जर के एक गांव गुड़ियानी में एक हवेली है, जहां इस समय सिवाय कबूतरों के, और कोई नहीं रहता। कुछेक कोनों में कुछ पुरानी पांडुलिपियां लाल कपड़ों में बंधी रखी थीं, अब शायद नहीं होंगी या वे गठरियां होंगी भी तो उनका रंग भी बदल चुका होगा। इन्हीं दिनों एक आत्मा भी वहां आती है और पूरे जनपद में चक्कर लगाकर लौट जाती है। यह दिव्य-आत्मा उस शख्स की है जो इसी हवेली की ओर, 'कोलकाता' से एक सेवादार के साथ रेल द्वारा चला था। यह संभवतः 13-14 सितम्बर, 1907 की घटना है। उसके साथ उसकी एक संदूकची थी, जिसमें कुछ किताबें, कुछ कोरे कागज, कुछ अखबारों की कतरनें, दो टोपियां, दो-तीन जोड़ी कुर्ते-पायजामे व एक छोटी सी सरस्वती प्रतिमा व एक जोड़े तौलिया-मौजे व एक जोड़ी चप्पल थीं। साथ ही दैनिक पूजा-अर्चना के लिए तांबे की एक प्लेट, घंटी व धूपदान भी था। जब वह शख्स कलकत्ता से चला था तब से उसे तेज बुखार था। सांस उखड़ी हुई थी, उस पर लम्बी यात्रा। एक ही तड़प थी कि किसी तरह अपनी जन्मस्थली पहुंच जाए और वहां पुरखों की हवेली में ही अंतिम दिन कुछ लिखते-लिखाते कटें। मगर रेल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंची। उस समय गांव की ओर जाने का कोई साधन नहीं था। सेवक उसे किसी तरह रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक धर्मशाला तक ले आया। मगर मैनेजर ने जब देखा कि रात बिताने के लिए आने वाले शख्स की सांसें उखड़ रही हैं, फतेहपुरी में तो उसने धर्मशाला में कमरा देने से भी इन्कार कर दिया। तब तक सर्दी का मौसम भी दस्तकें दे चुका था। सेवक ने मुश्किल से अपने स्वामी को उसी धर्मशाला के बाहरी बरामदे में लिटा दिया। एक कम्बल उढ़ा दिया और उसी रात किसी क्षण उस दिव्य पुरुष ने 'हरि ओम' कहते हुए अंतिम सांस ली। अधखुली आंखों में उस पुश्तैनी हवेली का चित्र था, जहां वह दिव्य पुरुष पहुंच नहीं पाया। अगले दिन पौ फटने से पहले ही उस सेवक ने एक पुराने जमाने की जीप का सहारा लिया। जीप-ड्राइवर को अपनी जेब की सारी राशि दी और कम्बल में लिपटे उस दिव्य शव को डालकर गांव तक ले आए। वहां गांव वाले एक आवाज पर 'बाबू जी, बाबू जी' कहते एकत्र हो गए। पंचायती निर्णय हुआ कि अंतिम-क्रिया विधिपूर्वक हो। उस समय परिजन भी आ पाए या नहीं, यह तो पता नहीं चला लेकिन उस दिव्य पुरुष, जिसकी कलम से लार्ड कर्जन सरीखा वायसराय भी कांपता था, की अंतिम-क्रिया हुई। उस शख्स ने लगभग 16 कृतियां दी थीं, 'हिन्दुस्तान' (कालाकांकर) का सम्पादन किया था। कलकत्ता में उस समय के सबसे बड़े दैनिक 'भारतमित्र' का भी सम्पादन किया था। लाहौर से छपने वाले 'कोहेनूर' (उर्दू पत्र) व 'अखबारे चुनार' (उर्दू) का भी सम्पादन किया था। उनकी चर्चित रचनाओं में 'शिवशम्भू के चिट्ठे' के इलावा उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी भी शामिल थी। उसके प्रशंसकों के हिंदी के महान विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पत्रकार महाराय कृष्ण, उर्दू के अदीब मंटो, शायर अहमद नदीम कासमी व फैज भी शामिल थे। 42 वर्ष की अल्पायु में ही अंतिम सांस लेने वाले इस दिव्य लेखक बाबू बाल मुकन्द गुप्त की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने वालों में उनकी स्मृति में एडवोकेट नरेश चौहान के नेतृत्व में दर्जनभर दीवानों कर एक शोध संस्थान भी स्थापित किया। वर्ष में दो बार समारोहों की परंपरा आरंभ की। यहां प्रदेश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने यहां आने व इस हवेली को एक राष्ट्रीय स्मारक का रूप देने की घोषणाएं कीं। मगर एक मुख्यमंत्री के इलावा शेष कोई भी नहीं आ पाया।

ऐसी दिव्य आत्माएं अभिशाप तो नहीं देतीं, मगर श्राद्धों के दिनों अपनी जन्मस्थली तक आती तो हैं। उनकी इतनी अपेक्षा कभी-कभी कचोटती अवश्य है। इस दिव्य आत्मा का नाम था, प्रख्यात साहित्यकार व पत्रकार 'बाबू बाल मुकुन्द गुप्त'। परिजन अब भी कलकत्ता में रहते हैं। बाबू जी का श्राद्ध कर्म होता होगा मगर शेष भटकाव अभी जारी है। श्राद्धों के दिनों में यदि पितर धरती पर उतरते हैं तो यह मान कर चलना चाहिए कि रेवाड़ी के समीप गांव गुड़ियानी में भारत के हिंदी पत्रकारिता के महानायक बाबू बाल मुकुंद गुप्त की आत्मा भी अपनी धीरे-धीरे ध्वस्त हो रही हवेली के आसपास होगी। इसी हवेली में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पहली बार आंखें खोली थीं। यहीं से पंडित मदन मोहन मालवीय, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें पहले कालाकांकर और फिर लाहौर व कलकत्ता (अब कोलकाता) ले गए थे। इसी गांव के परिवेश में व जनपद में अपनी शुरुआती शिक्षा-प्राप्ति के दौरान ही गुप्त जी ने लिखना शुरू कर दिया था। कुछ लेख छपे तो लेखनी की सुगंध आसपास फैलने लगी। कालाकांकर में उन्हें वहां से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दोस्तान' का सम्पादन-कार्यभार मिला और जब ख्याति फैली तो 'कोहेनूर' में चले गए। लेखों की धूम का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहां से कलकत्ता में 'भारत-मित्र' और बंगबंधु के सम्पादक पद की पेशकश आई तो वहां चले गए। वहां सम्पादन कार्य चुनौतीपूर्ण भी था और ढेरों उम्मीदें भी लगाई जाती थीं एक सम्पादक से। उन दिनों ऐसा पहली बार हुआ था कि तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने अपने स्टाफ को, बाबू बाल मुकुंद गुप्त के सम्पादकीय लेखों और उनके नियमित स्तम्भ 'शिव शम्भू के चिट्ठे' का अंग्रेजी अनुवाद दैनिक आधार पर उन्हें भेजने का आदेश दिया था। कलकत्ता-प्रवास के मध्य हिंदी के महान विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त का टकराव हो जाया करता था लेकिन अधिकांश अवसरों पर द्विवेदी जी को ही झुकना पड़ता था। कहां गुड़ियानी का ग्रामीण युवा पत्रकार और कहां भाषा-मर्मज्ञ आचार्य द्विवेदी। बहरहाल, खूब चर्चा होती गुप्त जी की। इसी बीच उन्होंने बंगला की कृतियों के हिंदी अनुवाद का सिलसिला भी शुरू कर दिया। काम के बोझ से शरीर शीघ्र ही हारने लगा था। एक बार उनको लगा कि अब लम्बी पारी नहीं खेल पाएंगे तो उन्होंने अपने गांव गुड़ियानी लौटने का मन बना दिया। कोलकाता से तो यही कहकर अवकाश लिया था कि वापिस लौट आएंगे लेकिन मन में यही आशंका थी कि शायद शरीर इतना श्रम झेल नहीं पाएगा। पिछले कुछ दशकों से बाबू जी के दीवाने हर वर्ष उसी हवेली में हवन करते हैं और फिर शहर में एक समारोह। मगरअब धीरे-धीरे हवेली की हालत खराब होने लगी है और जहां बैठकर बाबू जी कलम-क्रांति करते थे वह स्थल भी ध्वस्त होने लगा है। वंशज कोलकाता में रहते हैं। एक प्रवीन विमल गुप्त सरकार को बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि यह हवेली सरकार ले ले और कोई स्मारक बन जाए। कुछ दीवाने लोग हैं एडवोकेट नरेश चौहान, रोहित यादव, ऋषि सिंहल, सत्यवीर नाहड़िया और प्रवीण खुराना जैसे जो अब भी अपने दायित्व और लगाव से बंधे हुए हैं। ढेरों प्रश्न हैं जो अभी भी उत्तर के मोहताज हैं। पहला यह कि इस हवेली का अधिग्रहण क्यों नहीं हो पा रहा?

दूसरा यह कि क्या युवा पीढ़ी अभी भी इस महान युगपुरुष के साथ भावनात्मक या विचारात्मक रूप से जुड़ी हुई है? तीसरा यह कि बाबू जी पर ग्रंथावलियां तो छपीं लेकिन क्या इस जनपद के शिक्षा संस्थानों तक पहुंच पाईं? चौथा उन परिस्थितियों पर शोध, जिनमें बाबू जी मात्र चार दशक (42 वर्ष) ही जी पाए। उनके महाप्रयाण के बारे में कोई पुख्ता विशेष विवरण अभी भी नहीं मिलता।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सात पॉकेटमला एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/00882)

महिलाएँ स्वस्थ होंगी तो पीढ़ियाँ होंगी सुरक्षित- सीएमओ

बहराइच।

जिले में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान' चलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि जब महिलाएँ स्वस्थ होंगी तो आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित और सशक्त होंगी और परिवार में समृद्धि आएगी। इसी उद्देश्य से जिले के 411 स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष जांच, परामर्श और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें एक दिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी। अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

17 सितम्बर से चलेगा 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान'- मातृत्व और महिला स्वास्थ्य पर रहेगा विशेष जोर

(सीएचसी) चित्तौरा में सांसद आनंद गोंड करेंगे। वहीं जिले के अन्य सीएचसी पीएचसी व आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जायेगा। मुख्य

चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शर्मा ने बताया कि यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण माह के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत एक ही छत के नीचे 12 प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएमओ ने बताया कि अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में गर्भावस्था देखभाल, टीकाकरण उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दिल की बीमारियों की जांच-उपचार, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच,किशोरियों और महिलाओं के लिए एनीमिया की जांच, परामर्श एवं उपचार, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए टीबी की जांच, जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल रोग की जांच, एससीडी कार्ड वितरण एवं परामर्श की सेवाएँ दी जायेंगी। इसके आलावा पोषण सुधार और मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, आयुष चिकित्सा सेवाएँ और रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे।

डीएचईआईओ बृजेश सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक दिन स्त्री रोग, नेत्र, ईएनटी, त्वचा, मानसिक स्वास्थ्य और दंत रोग विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इसके लिए रोस्टर तैयार किया गया है और जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम के चिकित्सकों व निजी अस्पतालों का सहयोग लिया जाएगा। सभी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रतिदिन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर भारत सरकार को भेजी जाएगी। डीसीपीएम मो0 राशिद ने बताया अभियान के तहत गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर रैलियाँ, स्कूल कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत जन आंदोलन को भी शामिल किया गया है, जिसमें ÷निक्षय मित्र÷ नामांकन का विस्तार किया जाएगा और सामुदायिक स्तर पर लोगों को टीबी रोगियों की मदद और पोषण समर्थन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिलाध्यक्ष कांग्रेस राजेश दीक्षित जी का जन्मदिन समारोह बड़े हर्ष उल्लास के साथ कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया

बांदा।

जिला कांग्रेस कमेटी स्टेशन रोड कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित जी का जन्मदिन समारोह कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ संजय द्विवेदी दनादन की अध्यक्षता में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सभी कांग्रेसियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित एक दूसरे का मुंह मीठा करा कर जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई अपने जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आवाहन किया गया की पार्टी नेतृत्व में जिस विश्वास के साथ मुझे जिले की कमान सौंपी है आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए आप द्वारा पार्टी के चतुर्मुखी उत्थान के लिए जो मेहनत की जा रही है उसी का नतीजा है कि जिले के कोने-कोने तक बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हो रही है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा खान ने कहा की वर्तमान सरकार सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर फेल है उन्होंने तीन माह पूर्व जिला थाना क्षेत्र अंतर्गत अबोध बालिका के साथ हुए बलात्कार को लेकर न्यायालय, पुलिस अधिकारियों एवं पत्रकारों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने स्वतंत्र कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य किया गया शहर अध्यक्ष अफसाना शाह ने जिला अध्यक्ष जी को मुंह मीठा कराया व दीर्घायु होने की कामना की, वैश्य राजेश कुमार गुप्ता पप्पू ने कहा तपस्या और संघर्ष का नाम ही राजेश दीक्षित है इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी शिवबली सिंह,सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गोयल जी,जिला महामंत्री/ मीडिया प्रभारी सत्य प्रकाश द्विवेदी एड, महामंत्री शोयब रिज़्वी, कालीचरण निगम, जिला प्रवक्ता सुमन शुक्ला, धीरेंद्र पाण्डे धीरू, के पी सेन,आरिफ निजामी,हेमंत सिंह वर्मा,सभासद इरफान खान, सुखदेव गांधी,प्रमोद यादव, वारिस अली आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

दीवानी न्यायालय परिसर में विधि पुस्तकों, वाद पत्रों, परिवाद पत्रों व निर्णयों की लगाई गई प्रदर्शनी

बहराइच। स्थानीय दीवानी न्यायालय परिसर में विधि पुस्तकों, वाद पत्रों, परिवाद पत्रों व निर्णयों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। सभी न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने घूम घूमकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में न्यायिक अधिकारियों, बार ऐसोसिएशन एवं हिंदी विधि प्रतिष्ठान के सामूहिक सहयोग से तमाम विधि पुस्तकों विशेष वाद पत्रों एवं विशेष निर्णयों को इकठ्ठा कर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने किया एवं आज की व्यवस्था वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सिंह पम्मू एवं बृजेंद्र सिंह ने किया।मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने कहा कि भाषा में नम्रता होनी चाहिए जो हिंदी भाषा में पूर्णतः परिलक्षित है। हम मां भारती के पुत्र है और हिंदी की सेवा करके हम मातृ ऋण से मुक्त हो।

अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि शंकर के डमरू से उत्पन्न संस्कृत भाषा के मूल तत्वों से उपजी हिंदी हमारी संस्कृति का द्योतक है। अधिवक्ता संजय तिवारी ने कहा कि दूसरे की भाषा जानना सम्मान की बात है किंतु अपनी भाषा की अज्ञानता निराश होने की बात है।

अधिवक्ता हरीश शर्मा ने कहा कि शिकागो में विवेकानंद और संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी बाजपेई ने हिंदी की धाक जमाई। अपर जनपद न्यायाधीश राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं बल्कि भाषाओं में स्पर्धा से था। जनपद अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम जी बाजपेई ने कहा कि कुंभ के महाआयोजन से हमारी भाषा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। मीडिया प्रभारी अनिल त्रिपाठी ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की विधि शब्दावली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।अंत में संस्थान के अध्यक्ष राम छबीले शुक्ला ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर जनपद न्यायाधीश पवन शर्मा, अनिल कुमार, आनंद शुक्ल, अरविंद गौतम, प्रतिभा चौधरी, तूबा फातिमा, शिवाली मिश्रा, रूपाली तिवारी , गया प्रसाद मिश्रा, विजय पाठक, पंकज मिश्रा, दिनेश तिवारी, शिवेंद्र सिंह, अभिषेक प्रताप सिंह, राम सूरत वर्मा, काशी नाथ शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी सहित तमाम हिन्दी प्रेमी मौजूद थे।

विद्यार्थियों को दी गई रक्षा सेनाओं की संगठनात्मक जानकारी

मुरादाबाद।

रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग हिन्दू कालेज और 24वीं बटालियन एनसीसी की कालेज यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में रक्षा अध्ययन विभाग के स्मार्ट-क्लास में चल रही व्याख्यानमाला के दूसरे दिन डॉ. चंद्रजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन हिन्दू कालेज मुरादाबाद और प्रो0 आनंद के. सिंह प्रभारी रक्षा अध्ययन विभाग ने संयुक्त रूप से भारत के रक्षा संगठन और उसकी संरचना विषय पर बतौर अतिथि व्याख्याता अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस व्याख्यान में रक्षा अध्ययन विषय और एनसीसी के कैडेट्स शामिल हुए। डॉ. चंद्रजीत ने बताया कि भारत के रक्षा संगठन में रैंकिंग का अपना विशेष महत्व होता है। आप बैज देखकर रैंक को पहचान लेते हैं। उन्होंने आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तीनो सेनाओं में समतुल्य रैंक की पहचान करने का गुण भी सिखाया। इस अवसर पर प्रभारी रक्षा अध्ययन प्रो. आनंद ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल मे ही सेनाओं में रैंकिंग व्यवस्था है। भारत की प्राचीन युद्धकला के अंतर्गत भी सैनिकों और युद्धाओं के पास उस वक्त के हिसाब से रैंक प्राप्त था। अर्धरथी, रथी, अतिरथी, महारथी आदि रथ सेना में योग्यता के आधार पर निर्धारित होते थे। ऐसे ही गज सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना के अपने अपने क्रम थे। इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य एनसीसी और रक्षा अध्ययन के विद्यार्थियों को रक्षा सेनाओं की सम्पूर्ण संगठनात्मक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अपना कॅरियर निर्माण के लिए भी तैयार करना भी है। व्याख्यानमाला का संचालन कैप्टन राजीव चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. मो. साकिब, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अनुपमा मिश्रा, डॉ. मदन मोहन शुक्ला, डॉ. आलोक यादव और डॉ. चरण सिंह मौजूद रहे।

रक्तदान कर भाजपा मनाएगी मोदी जी का जन्मदिन

बांदा।

प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल नन्दी करेंगे सेवा पखवाड़ा का शुभारम्भ 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम

भारतीय जनता पार्टी बांदा द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रभारी मंत्री नन्द गोपाल नन्दी जी फीता काटकर करेंगे द्य भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्नातक एम एल सी चुनाव 2026 की बाँदा विधानसभा की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से गाँधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है जिसके प्रथम दिन 17 सितम्बर को प्रातः 9 बजे महाराणा प्रताप चौक में स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा तत्पश्चात जिला अस्पताल परिसर स्थित मंदिर में अखंड पाठ व रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा द्य इसके बाद जिला अस्पताल (महिला व पुरुष) में मरीजों को फल वितरित किये जायेंगे द्य इसी दौरान अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जायेगा द्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नन्दी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे द्य पूर्व जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता अशोक त्रिपाठी जीतू ने कहा कि यदि एम एल सी चुनाव को जीतना है तो काम को धरातल पर करना होगा ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने होंगे द्य जिला संयोजक धर्मेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि सभी लोग अभी से घर घर जाकर मतदाता बनाने का कार्य शुरू कर दें प्रत्येक बूथ से कम से कम 10 व सेक्टर से 200 वोट बनाने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने सभी से उम्मीद की है कि वे उक्त लक्ष्य को पूरा कर पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे।

कार्यशाला में सेवा पखवाड़ा के जिला संयोजक संतोष गुप्ता संतू, मतदाता पुनरीक्षण अभियान के जिला संयोजक उत्तम सक्सेना, धीरेन्द्र सिंह, राजेश सिंह परिहार, प्रधानाचार्य जमुना प्रसाद पाण्डेय, ममता त्रिपाठी, अखिलेश नाथ दीक्षित, निखिल सक्सेना, मनीष गुप्ता, राजेश गुप्ता , संतोष राजपूत, राजेश गुप्ता रज्जन आदि मौजूद रहे।

वन स्टॉप सेंटर की काउंसिलिंग से टूटने से बचा अंजलि का परिवार

मुरादाबाद।

वन स्टॉप सेंटर मुरादाबाद की सक्रियता और काउंसिलिंग से अंजलि (काल्पनिक नाम) का परिवार बर्बाद हो जाने से बच गया। सेंटर मैनेजर गुंजन शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले अंजलि ने वन स्टॉप सेंटर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति काफी समय से मारपीट और मानसिक शोषण कर रहे हैं। ब'चों के पालन पोषण का खर्चा नहीं दे रहे हैं और न ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। काउंसलर तनिषा दिवाकर और टीम द्वारा अंजलि की शिकायत के आधार पर उनके पति को वन स्टॉप सेंटर बुलाकर उनके द्वारा ऐसा किए जाने के कारणों के बारे में जानकारी ली गई और उन्हें विभिन्न प्रकार के उदाहरण और पारिवारिक मूल्यों का हवाला देते हुए कई बार काउंसिलिंग की। काउंसिलिंग के बाद उनके पति ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में अपने पूरे परिवार का बेहतर तरीके से ध्यान रखने की जिम्मेदारी स्वीकार की।

मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, चुराचांदपुर में कुकी नेता के घर में लगाई गई आग

चुराचांदपुर/इंफाल । मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में रविवार देर रात हिंसा भड़क गई जब एक कुकी समुदाय के बड़े नेता का घर भीड़ ने कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। अधिकारियों के मुताबिक, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के नेता कैल्विन ऐकेंथांग का घर रविवार देर रात जला दिया गया। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इसमें किसी हमले का हाथ नहीं है। इसी दौरान, एक और कुकी नेता गिंजा वुआलजोंग के घर को भी निशाना बनाया गया।

130वें संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक दुर्भावनापूर्ण, इसके पीछे असली खेल की मंशा- खरगे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को दावा किया कि 130वें संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक के पीछे असली खेल की मंशा हो सकती है क्योंकि यदि किसी भी मुख्यमंत्री को 30 दिन जेल में रहने पर पद से हटा दिया जाए तो फिर चुनाव की चिंता क्यों होगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चुनावी सुधार के नाम पर लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है। खरगे ने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 'एक्स पर पोस्ट किया, पिछले 11 वर्षों में आरएसएस-भाजपा द्वारा भारत के लंबे समय से पोषित और कड़ी मेहनत से निर्मित लोकतंत्र को खोखला करने का षड्यंत्रकारी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी हेराफेरी को सुधार का जामा पहनाकर, संविधान में निहित सबसे महत्वपूर्ण मतदान के अधिकार को छीनने के लिए एक हथियार के रूप में

इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से लाखों लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को मताधिकार से वंचित करने से लेकर राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई निंदनीय वोटचोरी तक, भाजपा ने लगातार और रणनीतिक रूप से चुनावों की शुचिता को खत्म कर दिया है। खरगे का दावा है, असली खेल 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में हो सकता है। यह प्रस्ताव केंद्र को चुनी हुई राय सरकारों को भ्रष्ट करार देकर गिराने की अनुमति देता है, जिसका आकलन पहले से ही भाजपा की पकड़ वाली एजेंसियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उनका आरोप है कि यह विधेयक दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों के भीतर कानूनी तौर पर बर्खास्त कर सकते हैं तो चुनाव की चिंता क्यों करें? इसका संदेश यही प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, इसलिए, इस अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर, आइए, हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस-भाजपा के चंगुल से बचाने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, 'संघ राय क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और यह समिति अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करेगी।

रफ़्तार बीएमडब्ल्यू का कहर! वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत, रसूखदार महिला ड्राइवर गिरफ्तार

नई दिल्ली । रविवार दोपहर हुई एक जानलेवा दुर्घटना में शामिल बीएमडब्ल्यू चला रही महिला गगनप्रीत कौर को कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दुर्घटना में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई और उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह दुर्घटना रिंग रोड पर धौला कुआं के पास हुई जब तेज़ रफ़्तार बीएमडब्ल्यू उस मोटरसाइकिल से टकरा गई जिस पर दंपति सवार थे। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह गिरफ़्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा जाँच के बाद जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ़ अस्पताल में की गई, जहाँ दुर्घटना के बाद महिला चालक और उसके पति दोनों को भर्ती कराया गया था। सिंह और उनकी पत्नी को भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ बाद में सिंह की मृत्यु हो गई। गगनप्रीत 38 वर्ष की हैं और उनकी शादी 40 वर्षीय परीक्षित मक्कड़ से हुई है, जो दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास हुई दुर्घटना के समय उनके साथ

कार में मौजूद थे। पता चला है कि यह दंपति गुरुग्राम में रहता है और लग्ज़री उत्पादों का व्यवसाय करता है। परीक्षित का भी नाम एफआईआर में दर्ज है। 52 वर्षीय नवजोत सिंह केंद्रीय वित्त मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कल अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा में दर्शन किए। इसके बाद दोनों ने आरके पुरम स्थित कर्नाटक भवन में दोपहर का भोजन किया और घर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। संदीप ने पुलिस को बताया कि बीएमडब्ल्यू कार तेज़ गति से चल रही थी और उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारने के बाद पलट गई। नवजोत और संदीप को एक वैन में अस्पताल ले जाया गया और गगनदीप उनके साथ थी। संदीप ने पुलिस को बताया कि वह गगनप्रीत से उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाने के लिए कहती रही, लेकिन उसने वैन चालक - गुलफाम नाम के एक नेकदिल व्यक्ति - को दुर्घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ़ अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पुलिस सूत्रों ने अब बताया है कि गगनप्रीत के पिता अस्पताल के सह-मालिक हैं और इस बात की जाँच की जा रही है कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा है कि सभी नियमों का पालन किया गया, लेकिन गगनप्रीत का अस्पताल मालिकों से कोई संबंध है, इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार, पुलिस को संदेह है कि गगनप्रीत, मेडिकल रिपोर्ट सहित सबूतों से छेड़छाड़ करने के इरादे से नवजोत और संदीप को न्यूलाइफ़ अस्पताल लेकर आई थी।

परिवार न्याय की मांग कर रहा है

सिंह परिवार न्याय की मांग को लेकर मुखर रहा है, और रिश्तेदारों ने दुर्घटना के बाद दंपति के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताई है। सिंह की भाभी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम सदमे में हैं। अगर मेरे देवर को पास के अस्पताल ले जाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी। हम उनके और मेरी भाभी, जिनकी हालत भी गंभीर है, के लिए न्याय चाहते हैं।

यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, वीसी को बायोडाटा में बताना होगा अपना सच

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलती करने वाले को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के विवरण सहित उसके फैसले को कुलपति के बायोडाटा का हिस्सा बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ शिकायत की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी यह उन्हें हमेशा के लिए परेशान करे। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पश्चिम बंगाल स्थित एक विश्वविद्यालय के एक संकाय सदस्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने दिसंबर 2023 में कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के उस फैसले को बहाल करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता की शिकायत समय सीमा पार कर चुकी है और खारिज किए जाने योग्य है। पीठ ने कहा कि गलती करने वाले को माफ कर देना उचित है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए। अपीलकर्ता (संकाय सदस्य) के खिलाफ जो गलती हुई है, उसकी तकनीकी आधार पर जांच नहीं की जा सकती, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा, इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 (वीसी) द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की घटनाओं को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अपराधी को हमेशा के लिए परेशान करने दिया जा सकता है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय को प्रतिवादी संख्या 1 के बायोडाटा का हिस्सा बनाया जाए, जिसका अनुपालन वह व्यक्तिगत रूप से सख्ती से सुनिश्चित करे।÷ शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने दिसंबर 2023 में एलसीसी में वीसी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर में गैंगस्टरों के 25 ठिकानों पर छापे, 380 पुलिसकर्मी तैनात, हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद

नई दिल्ली । द्वारका जिला पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में 25 ठिकानों पर छापेमारी करके साल के सबसे बड़े गिरोह-विरोधी अभियानों में से एक को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में द्वारका के डीसीपी की निगरानी में 25 पुलिस टीमों और 380 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कुल छापेमारी स्थलों में से 19 दिल्ली में और 6 हरियाणा-एनसीआर में थे। इस अभियान में विशेष रूप से कपिल सांगवान उर्फ नंदू और विक्की टक्कर के आपराधिक नेटवर्क को निशाना बनाया गया, जिन पर जबरन वसूली, हत्या और हथियारों की तस्करी के कई आरोप हैं। 25 छापेमारी स्थलों में से 19 दिल्ली में और 6 हरियाणा-एनसीआर में थे। यह कार्रवाई कपिल सांगवान उर्फ नंदू और विक्की टक्कर के आपराधिक नेटवर्क पर केंद्रित थी, दोनों ही जबरन वसूली, हत्या और हथियारों की तस्करी सहित कई हाई-प्रोफाइल अपराधों के लिए पुलिस की नज़र में रहे हैं।

छापेमारी के दौरान क्या बरामद हुआ?

पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकदी, हथियार और विलासिता की वस्तुओं का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। 35 लाख नकद, लगभग ?50 लाख मूल्य के सोने के आभूषण, 8 पिस्तौल, 29 ज़िंदा कारतूस और 3 मैगज़ीन, एक बुलेटप्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक ऑडी कार (PB 13 BN 0004), 14 महंगी लग्ज़री घड़ियाँ, लैपटॉप, आईपैड, एक कैश गिनने की मशीन और वॉकी-टॉकी सेट।

26 हिरासत में, 6 गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 6 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जाँचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्धों का नंदू या विक्की टक्कर गिरोह से सीधा संबंध है। यह कार्रवाई कई जिलों में सक्रिय इन गिरोहों के प्रभाव को कमज़ोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई हाई-प्रोफाइल शूटर और गिरोह के सदस्य शामिल हैं। नंदू गिरोह का एक शूटर पवन उर्फ प्रिंस (18) राजमंदिर स्टोर और छावला फायरिंग मामलों से जुड़ा था। विक्की टक्कर गिरोह के हिमांशु उर्फ मछी (24) के खिलाफ सात मामले लंबित हैं। एक अन्य आरोपी प्रशांत, नंदू गिरोह से संबंधित है और उस पर 11 मामले दर्ज हैं। विक्की टक्कर गिरोह का सदस्य राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत (25) 20 एफआईआर में नामजद है। अंकित ढींगरा उर्फ नोनी (34) पर 10 मामले दर्ज हैं, जबकि प्रवीण उर्फ डॉक्टर 25 से ज़्यादा आपराधिक मामलों के साथ सबसे कुख्यात है।

हिरासत में नाबालिग को यातना, सुनवाई से सुप्रीम इनकार; याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात पुलिस पर 17 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण और कस्टडी में यातना का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। मामले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, हमें आपकी परेशानी का एहसास है, लेकिन आपने पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वकील ने बताया कि नाबालिग के साथ पुलिस ने बर्बरता की है। इस पर कोर्ट ने दोबारा पूछा, आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वकील ने दलील दी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एम्स, नई दिल्ली, से मेडिकल बोर्ड बनवाकर नाबालिग के जख्मों की जांच कराने का निर्देश देने की मांग

की थी। इस पर कोर्ट ने कहा,क्या हाई कोर्ट यह आदेश नहीं दे सकता? वकील ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक मामले की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में नाबालिगों को पुलिस कस्टडी में उठाकर प्रताड़ित करने का बड़ा मुद्दा है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पहले हाई कोर्ट में जाएं और अगर वहां राहत न मिले तो वापस सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एम्स से मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। वकील ने यह भी चिंता जताई कि जब तक वह हाई कोर्ट पहुंचेंगे, तब तक बोटाद थाने की सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर आप समय पर हाई कोर्ट जाएंगे तो फुटेज नष्ट नहीं होगी। इसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली। यह याचिका नाबालिग के बहन ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 18 अगस्त को गुजरात के बोटाद शहर की पुलिस ने नाबालिग को सोने और नकदी की चोरी के शक में उठाया। नाबालिग को 19 अगस्त से 28 अगस्त तक गैरकानूनी तरीके से कस्टडी में रखा गया। इस दौरान उसे पुलिस स्टेशन में बेरहमी से पीटा गया और यौन शोषण किया गया। पुलिस ने नाबालिग को न तो 24 घंटे के भीतर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और न ही मेडिकल जांच कराई।